



SHL/SEC/2021

July 24, 2021

The Bombay Stock Exchange Limited
Listing Department,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
Phiroze JeeJeeBhoy Towers, Dalal Street, Fort
Mumbai – 400 001.

The Calcutta Stock Exchange Ltd.
7, Lyons Range
Kolkata - 700 001 India

Company Code: 537253

Dear Sir/Ma'am,

Sub.: Newspaper clipping regarding publication of Un-Audited Financial Result for 01th quarter ended on June 30, 2021 of the FY 2021-22.

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published **Un-Audited Financial Result for 01th quarter ended on June 30, 2021 of the FY 2021-22** in newspapers viz. Pioneer on July 23, 2021 both Hindi & English edition.

In this regard, please find enclosed newspapers clipping of the result published on July 23, 2021 and oblige.

Thanking you,

Yours sincerely,

For SUNIL HEALTHCARE LIMITED

**SANTOSH KUMAR SHARMA
COMPANY SECRETARY**

F6817

Date:24.07.2021

Place: New Delhi

Encl: a/a

Sunil Healthcare Ltd.

38E/252-A, Vijay Tower, Opp Panchsheel Park Comm. Complex, New Delhi -110049

T: +91 -11-49435555/00, F: +91 -11-43850087 Email : info@sunilhealthcare.com, Web: www.sunilhealthcare.com

CIN No. : L24302DL1973PLC189662

कोंकण में बारिश से रेल सेवा प्रभावित, 6000 यात्री फंसे



पड़ोसी रायगढ़ जिले में भी इसी प्रकार कुंडलिक, अंबा, सावित्री, पातालगांगा, गढ़ी, उल्हास सहित प्रमुख नदियां खतरे के निशान से उमर बह रही हैं। समीक्षा बैठक के दौरान ठाकरे ने बताया कि आईएमडी ने अगले तीन दिनों तक इस क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक बुधवार को रात सवा दस बजे मध्य रेलवे ने मुंबई से 120 किमी दूर कसाग के पास अंबरमाली स्टेशन के पास पटरियों पर बहुत ज्यादा पानी भर जाने और कसाग घाट पर पथर टूटकर गिरने की घटनाओं के बाद टिडवाला और इगतपुरी रेल खंड के बीच मध्य रेलवे ने यातायात निलंबित कर दिया। बाद में दो रात 12 बजकर 20 मिनट पर मध्य रेलवे ने मुंबई से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित वंगानी स्टेशन के पास बाढ़ आने और खंडला घाट खंड में कुछ पथरों के गिरने के बाद अंबरमाली और लोनावला के बीच यातायात रोक दिया।

महाराष्ट्र में भारी बारिश ने कई इलाकों में मचाई तबाही, नदियां उफान पर

भाषा। मुंबई

महाराष्ट्र में भारी बारिश और नदियों में उफान आने से कोंकण रेलवे मार्ग पर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं और करीब छह हजार यात्री फंस गए। भारी बारिश की वजह से मुंबई सहित राज्य के कई अन्य हिस्सों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से अधिकारियों को बचाव कार्य में प्रशासन की मदद के लिए एनडीआरएफ को बुलानी पड़ी है। कोंकण रेलवे मार्ग प्रभावित होने की वजह से अबतक नौ रेलगाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है या रद्द किया गया है या उनके मार्ग को छोटा किया गया है। भारी बारिश की वजह से कोंकण क्षेत्र की प्रमुख नदियां रत्नागिरि और रायगढ़ जिले में नदियां खतरे के निशान से उमर बह रही हैं और सरकारी अमला प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुट है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगातार हो रही बारिश से इन दो तटीय जिलों में उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है। वहीं भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने तटीय क्षेत्रों के लिए अगले तीन दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सतर्क रहने और नदियों के जलस्तर पर नजर रखने एवं बड़े लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। कोंकण रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मार्ग पर

व्यवधान के कारण नौ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया, उन्हें गंतव्य से पहले रोक दिया गया है। भारी बारिश के कारण रत्नागिरि में चिपलून और कर्मठे स्टेशन के बीच वशिष्ठी नदी पुल का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस खंड पर ट्रेन सेवाएं अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, कोंकण रेल मार्ग पर 5,500-6,000 यात्री ट्रेनों में फंस गए हैं। कोंकण रेलवे का मुंबई के पास रोहा से मंगलुरु के पास स्थित थोकूर तक 756 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक मार्ग चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, क्योंकि यहाँ कई नदियां, घाटियां और पहाड़ हैं। चिपलून में बाढ़ की स्थिति के कारण नौ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया, उन्हें गंतव्य से पहले रोक दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। इनमें से दादर-सावंतवाडी स्पेशल ट्रेन को चिपलून स्टेशन और सीएसएमटी-मडगांव जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन को खेड स्टेशन की ओर मोड़ दिया गया है। कोंकण रेलवे के प्रवक्ता गिरीश कर्ंदीकर ने बताया कि इन ट्रेनों में सवार यात्री सुरक्षित हैं। तमाम परिस्थितियों के बावजूद कोंकण रेलवे यात्रियों को खाने-पीने का सामान मुहैया करवाया जा रहा है। जगबुड़ी, वशिष्ठी, कोडावली, शस्त्री, बाव समेत रत्नागिरि जिले की प्रमुख नदियां खतरे के निशान से उमर बह रही हैं। इसके परिणामस्वरूप खेड, चिपलून, लांजा, राजापूर, सांभोकर कस्बे और आस-पास के इलाके प्रभावित हुए हैं और इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सीएमओ के वक्तव्य के अनुसार



ईधन के बढ़ते दामों के विरोध में जम्मू में राज्यपाल का आवास घेरने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकती पुलिस

पनीरसेल्वम ने कहा सीएम व स्वास्थ्य मंत्री की बातों में विरोधाभास

चेन्नई। तमिलनाडु में विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने द्रमुक सरकार के इस कथन पर बृहस्पतिवार को सवाल उठाए कि केनेना वायस की दूसरी लहर के दौरान राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मौत नहीं हुईं। अन्नाद्रमुक की ओर से कहा गया कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तो कई माह में कुछ और ही कहा था। राज्य के चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री एम. सुब्रमण्यम ने बुधवार को कहा था तमिलनाडु में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। अन्नाद्रमुक के समन्वयक ओ. पनीरसेल्वम ने कहा कि यह सच्चाई को पूरी तरह से छिपाने जैसा है। प्रधानमंत्री के स्टालिन द्वारा लिखे पत्र का जिक्र करते हुए पनीरसेल्वम ने कहा कि उन्होंने ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए पीएम को पत्र लिखकर राज्य के लिए ऑक्सीजन आवंटन बढ़ाने की मांग की थी। पनीरसेल्वम ने कहा, तम मुख्यमंत्री ने कहा था कि तमिलनाडु में ऑक्सीजन की उपलब्धता की स्थिति बहुत ही विक्ट है और दो दिन पहले चेलापट्टूर (सस्कारी अस्पताल) में 13 लोगों की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह यह स्पष्ट करे कि प्रधानमंत्री को लिखे मुख्यमंत्री के पत्र की बात सच्ची है या फिर मंत्री का कथन सही है।

एनएचआरसी की रिपोर्ट के जवाब में हलाफनामा दे बंगाल सरकार: कोर्ट

भाषा। कोलकाता

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में चुनाव उपरांत हुई हिंसा के मामले में तैयार एनएचआरसी की रिपोर्ट पर हलफनामे के जरिए जवाब दाखिल करे। उच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कथित तौर पर लोगों पर हमले करने, घरों से भागने पर मजबूर करने और संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ दाखिल कई अनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने राज्य सरकार को 26 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। वहीं, इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर लगे आरोपों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य में स्थिति कानून के राज के बजाय राजा के राज जैसी है। सात सदस्यीय समिति ने 13 जुलाई को उच्च न्यायालय में अपनी रिपोर्ट जमा की, जिसमें अनुशंसा की गई है कि हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए और इन मामलों की सुनवाई राज्य से बाहर होनी चाहिए। एक

प्रतिवादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि एनएचआरसी की रिपोर्ट में अनियमितता है और इसमें अपराध के उन आरोपों को शामिल किया है जो दो माह के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले के हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रिपोर्ट में राजनीतिक पहलू की बू आ रही है। एक याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेटमलानी ने अदालत के समक्ष कहा कि एनएचआरसी की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की सही स्थिति को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ से अनुरोध किया कि हत्या और दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी को दी जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में राज्य में सत्तारूढ़ दल के समर्थकों द्वारा मुख्य विपक्षी पार्टी के लोगों पर प्रतिशोधात्मक हिंसा की भी चर्चा की है। वहीं, एनएचआरसी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक हिसाब चुकता करने के लिए निष्पक्ष एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और राज्य को बदनाम कर रही है।

महाराष्ट्र विधानसभा से एक साल के निलंबन को 12 भाजपा विधायकों ने न्यायालय में दी चुनौती

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के गणप 12 विधायकों ने पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्यवहार के लिए राज्य विस से एक साल के अग्रलेख निलंबन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। इन विधायकों को एक साल के लिए निलंबित करने के विस द्वारा पारित प्रस्ताव को चुनौती दी है। इन 12 विधायकों को पांच जुलाई को राज्य सरकार द्वारा विस अग्रलेख के विस ने पीठासीन अधिकारी महाराष्ट्र जायव के साथ दुर्यवहार करने के आरोप में एक साल के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया था। निलंबित किए गए 12 सदस्य संजय कुटे, आशीष शेलार, अजितकुमार पावट, गिरीश मलगाव, अतुल भातखलकर, परम अलगावनी, हरीश पिपले, रमेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुते, राज सतपुरे और बंटी मांगडिया हैं। इन विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल पटव ने पेश किया और ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। विधाय केनेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप को झूठ कर दिया था और कहा था कि घटना के बारे में जायव का विवरण एकरस था। फडणवीस ने कहा था, यह एक झूठ आरोप है और विधाय के सदस्यों की संख्या कम करने का प्रयास है क्योंकि हमने स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटे पर सरकार के झूठ को उजागर किया है। गणप सदस्यों ने पीठासीन अधिकारियों से दुर्यवहार नहीं किया। जायव ने इस आरोप की जांच करने की मांग की थी कि विधानसभा के कुछ सदस्यों और उन्हेले सुद अग्र टिप्पणी की थी और कहा था कि अगर यह सचिब होता है तो वह किसी भी राज का सामना करने के लिए तैयार है।

कामत और अलेमाओ के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश

पाजो। गोवा की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को लुइस बर्नर दिशत मामले में गन शोधन के संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और पूर्व लोक निर्माण विभाग मंत्री चरिल अलेमाओ के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए। मायूस की विशेष अदालत के न्यायाधीश रोडिग पॉल ने अपने आदेश में कहा कि कामत और अलेमाओ के खिलाफ आरोप तय किए जाएं। उन्हें 26 जुलाई को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। निदेशावली ने गोवा पुलिस की ओर से दर्ज क्वर्ड गई प्राथमिकी के आधार पर 2015 में धनशोधन संकथना अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद 2019 में जांच एजेंसी ने विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। ऐसे आरोप हैं कि अमेरिकन रिशत कंपनी लुइस बर्नर ने गोवा और गुवाबटी में दो प्रमुख जल विकास परियोजनाओं को पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को क्वड्रो स्याप की स्थित दी थी। जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेआईसीए) की ओर से वित्तपोषित 1,031 क्वड्रो स्याप की परियोजना को कामत नीत सरकार ने सत्ता में रहने के दौरान मंजूरी दी थी। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षिणी गोवा में जल की आपूर्ति बढ़ाना और राज्य के प्रमुख शहरो में सीवेज लाइन बिछाना था। राज्य पुलिस ने पहले इस मामले में अलेमाओ, जेआईसीए परियोजना निदेशक आनंद घाय्यादर और लुइस बर्नर के उपाध्यक्ष सत्यकाम मोदी की गिरफ्तार किया था। गोवा ने मंत्रियों ने जेआईसीए वित्तपोषित परियोजना को अनुबंध दिलाने के नाम पर 976,000 अमेरिकी डॉलर तक स्थित ने लिए।

सीबीआई पुलिस कर्मियों के स्थानांतरण, वाजे की बहाली की जांच कर सकती है : अदालत

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि सीबीआई महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके सहयोगियों के साथ गठजोड़ को लेकर पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण तथा बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की बल में बहाली की जांच कर सकती है। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जामदार की खंडपीठ ने कहा कि यह पुलिस आयुक्त का कर्तव्य है कि वह देश के कानून को लागू करें और वह किसी व्यक्ति के नहीं, बल्कि कानून के सेवक हैं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों और निलंबन के कई साल बाद 2020 में वाजे की बहाली से जुड़ी चीजों में यदि कोई गड़बड़ है तो यह जांच का विषय है। इसने इसके साथ ही देशमुख के खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के दो पैराग्राफ रद्द करने का आग्रह करने वाली महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी। इनमें एक पैराग्राफ राकेश नाता देशमुख के खिलाफ सचिन वाजे द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है। वहीं, दूसरा पैराग्राफ पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण और तैनाती में भ्रष्टाचार से संबंधित है। अदालत ने कहा, हमारे विचार में सीबीआई पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण और तैनाती तथा 15 साल बाद पुलिस बल में सचिन वाजे की बहाली के मामले में वैध रूप से जांच कर सकती है...। पीठ ने अपने आदेश में पुलिस आयुक्त के संदर्भ में भी टिप्पणी की। उल्लेखनीय है कि जब देशमुख राज्य के गृह मंत्री थे, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी परम बीर सिंह मुंबई के पुलिस आयुक्त थे। इस साल मार्च में, सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखकर देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसके विपरीत उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा इस साल पांच अप्रैल के अपने आदेश में देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच करने का निर्देश देने वाली टिप्पणियों को पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण और तैनाती की जांच करने के लिए एजेंसी को अनियंत्रित अधिकार दिए जाने के रूप में नहीं देखा जा सकता है।

सुनील हेल्थकेयर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

38ई/252-ए, विजय टावर, शाहपुरजाट, नई दिल्ली-110049

ई-मेल : info@sunilhealthcare.com, वेबसाइट : www.sunilhealthcare.com

सीआईएन: एल24302डीएल1973पीएलसी189662

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु पृथक्कृत एवं समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण (रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	पृथक्कृत				समेकित			
		3 माह समाप्त 30-06-2021	3 माह समाप्त 31-03-2021	3 माह समाप्त 30-06-2020	वर्ष समाप्त 31-03-2021	3 माह समाप्त 30-06-2021	3 माह समाप्त 31-03-2021	3 माह समाप्त 30-06-2020	वर्ष समाप्त 31-03-2021
		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित (नोट 2 देखें)	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	परिचालन से कुल आय	2,636.58	2,393.36	2,114.62	9,525.18	2,675.19	2,445.01	2,176.42	9,583.52
2	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले) - जारी प्रचालन से	37.09	15.20	1.64	34.94	31.81	(50.51)	(17.90)	(55.32)
	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले) - बंद प्रचालन से	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद) - जारी प्रचालन से	37.09	15.20	1.64	34.94	31.81	(50.51)	(17.90)	(55.32)
	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद) - बंद प्रचालन से	-	-	-	-	-	-	-	-
4	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर परश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद) - जारी प्रचालन से	27.50	6.87	0.06	27.53	20.84	(59.76)	(19.97)	(63.79)
	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर परश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद) - बंद प्रचालन से	-	-	-	-	-	-	-	-
5	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर परश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	27.50	6.87	0.06	27.53	20.84	(59.76)	(19.97)	(63.79)
6	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर परश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर परश्चात) शामिल हैं]	27.50	8.85	0.06	29.51	14.60	(39.37)	(21.68)	(88.08)
7	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रु. 10/-प्रत्येक)	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48
8	संचय (पुनर्प्राप्त संशय छोड़कर) जैसाकि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनापत्र में दर्शाया गया है	-	-	-	3,781.78	-	-	-	3,346.25
9	प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों के बाद) (रु. 10/- प्रत्येक का) - जारी प्रचालन से	0.27	0.07	0.00	0.27	0.20	(0.58)	(0.19)	(0.62)
	(क) मूल (रु.)	0.27	0.07	0.00	0.27	0.20	(0.58)	(0.19)	(0.62)
	(ख) तनुकृत (रु.)	0.27	0.07	0.00	0.27	0.20	(0.58)	(0.19)	(0.62)
10	प्रति शेयर अर्जन (असाधारण मदों के बाद) (रु. 10/- प्रत्येक का)	0.27	0.07	0.00	0.27	0.20	(0.58)	(0.19)	(0.62)
	(क) मूल (रु.)	0.27	0.07	0.00	0.27	0.20	(0.58)	(0.19)	(0.62)
	(ख) तनुकृत (रु.)	0.27	0.07	0.00	0.27	0.20	(0.58)	(0.19)	(0.62)

नोट्स :
 1. कोविड-19 वैश्विक महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यवसायिक माहौल में गंभीर अव्यवस्था पैदा कर दी है। इसके प्रभाव के संबंध में भारी अनिश्चितता है, जो इस समय समुचित निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तथापि, कम्पनी ने 30-06-2021 तक इसकी आस्तियों और देयताओं पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के साथ इन वित्तीय परिणामों के अनुमानों की स्थिति तक सभी घटनाओं तथा परिस्थितियों से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभाव का यथासंभव मूल्यांकन और विचार किया है। भावी आर्थिक हालात के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, कम्पनी का अनुमान है कि इन आस्तियों की वहन लागत से ऊपर जाएगी तथा इसके दायित्वों के निर्वहन हेतु यथेष्ट तरलता उपलब्ध है। ये अनुमान अनिश्चितता के अधीन हैं तथा वैश्विक महामारी की गंभीरता और अवधि द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। कम्पनी भावी आर्थिक हालात में महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर लगातार नजर रख रही है।
 2. 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु आंकड़े, पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षित आंकड़ों तथा पूर्ण वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक के लिए प्रकाशित वर्षागत अवधि के आंकड़ों के बीच संतुलनकारी आंकड़े हैं।
 3. पूर्व अवधियों के आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक है, उन्हें चालू अवधि वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किए हैं।
 4. उपरोक्त परिणामों का पुनरीक्षण लेखापरीक्षा समिति द्वारा और अनुमान निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2021 को सम्पन्न उनकी संबंधित बैठकों में किया गया था।

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21-07-2021

अनिल खेतान
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
सीआईएन : 00759951

COVID-19 China rejects WHO's plan to probe Wuhan lab leak

Beijing: China on Thursday categorically rejected the WHO's plan for the second phase of coronavirus origin-tracing in Wuhan, especially to probe the lab leak theory, as it dismissed reports that some of the employees of the facility were infected with the deadly virus before it spread to the city and the world.

China will not follow the World Health Organisation's suggested plan on the second phase of COVID-19 origin-tracing, Zeng Yixin, the vice minister of the National Health Commission (NHC), told a media briefing here.

The work plan on the second-phase origins study proposed by the WHO contains language that does not respect science, he said.

China's broadside against the WHO and its Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, who previously won Beijing's praise and support for praising President Xi

Jinping's handling of the coronavirus, came after he asked China to be transparent and provide raw data.

"Asking actually China to be transparent, open and cooperate, especially on the information, raw data that we asked for at the early days of the pandemic. We owe it to the millions who suffered and the millions who died to know what happened," he had said.

State-run Global Times reported that the WHO on Friday last proposed a second phase study into the origins of the coronavirus in China, which includes all the laboratories and markets in Wuhan.

Zeng said the plan has listed the hypothesis that China had violated lab regulations and leaked the virus as one of the major research objectives, and he was "very shocked" after reading the proposal, state-run China Daily reported.

Instead, the next-phase origin tracing should focus on var-

ious regions and countries, he said, reiterating Beijing's oft-repeated claim that the coronavirus broke out in several places in the world and China was the first to report about it in December, 2019 when it emerged in the central Chinese city of Wuhan.

Zeng said he was shocked by the WHO's work plan as it has been compromised by political manipulation and disrespect of scientific facts.

He said China had allowed the WHO experts to visit all places they wanted to go and meet all people they wanted to see early this year, adding that the results of the WHO-China joint study are able to stand the test of time.

"We hope the WHO can carefully consider the advice by Chinese scientists, take investigating the origin of the COVID-19 virus as a scientific question free from political interference," the vice minister said. **PTI**

Zulu leader makes plea to stop anti-India sentiment in SA

Johannesburg: Prince Mangosuthu Buthelezi, the traditional prime minister of the Zulu nation, has made an impassioned plea for an end to anti-Indian sentiment that has seen rising tensions between Indian-origin South Africans and their Black compatriots.

The tensions have been particularly high in the sprawling Indian township of Phoenix, north of Durban, and residents of three surrounding Black areas following the deaths of 22 people in Phoenix during the riots and looting last week by vigilante groups trying to protect their businesses and homes from looters.

The unrest started with protests after the jailing of former president Jacob Zuma on July 7, but rapidly degenerated into mass mob looting and arson allegedly fuelled by poverty and unemployment.

Zuma was sentenced to 15 months imprisonment by the country's apex court for contempt of court after he repeatedly refused to testify at the Commission of Inquiry into State Capture, where several witnesses have implicated him in corruption.

President Cyril Ramaphosa has called the incidents "a failed insurrection" in an organised way. Buthelezi said in an interview on TV channel Newzroom Afrika (sic) that Indians and Blacks had lived side-by-side for generations, as he decried the killings in Phoenix.

"This (the killings) is most unfortunate. The people who did this are very stupid, because they should have known beforehand what was likely to follow after that, that there would be feelings of wanting to retaliate," Buthelezi said.

"I've always lived cheek-by-jowl with the Indian people. Some of the Indians are committed to social cohesion, because there is no future if we don't promote and consolidate social cohesion," said the 92-year-old politician who started the mainly-Zulu Inkatha Freedom Party in 1975. **PTI**

Syria accuses Israel of carrying out strike, 2nd this week

Damascus: Syria accused Israel of carrying out an airstrike in a central province early on Thursday, the second such attack in as many days. The aerial attack caused material damage, it said.

The country's state news agency quoted an unidentified Syrian military official as saying the air defense systems shot down most of the missiles in the attack in the region of Quseir in Homs province. The report did not say what was targeted.

There was no immediate comment from Israel.

Neighbouring Lebanon's president, Michel Aoun, urged his foreign minister to protest with the United Nations the use of Lebanese airspace to carry out attacks on Syria. Lebanese media meanwhile reported that a rocket fell inside Lebanon — in Lahfed, a village in the north — on Thursday, causing a large crater in the ground.

Israel has launched hundreds of strikes against Iran-linked military targets in war-ravaged Syria over the years but rarely acknowledges or discusses such operations. Late Monday, Syria reported an Israeli airstrike near northern Aleppo province, but did not elaborate.

The Britain-based Syrian Observatory for Human Rights, a war monitor that has activists on the ground in Syria, said Monday's strikes targeted weapons depots belonging to Iranian-backed militiamen operating in Aleppo's Safira region.

The group also confirmed Thursday's strikes, saying they destroyed ammunition and weapons depots belonging to the Lebanese militant Hezbollah group in Homs. The Iran-backed group has been operating in Syria for years, siding with President Bashar Assad's forces in the devastating civil war and helping the government reclaim most of the country.

Separately, the Israeli military said it detained two people after they were seen crossing from south Lebanon into Israeli territory. **AP**

Merkel: No way back on German plan to end N power use

Berlin: Chancellor Angela Merkel on Thursday defended her decision to end Germany's use of nuclear power next year, but acknowledged that it will make it harder to reduce greenhouse gas emissions in the short term.

The decision, taken in the wake of the Fukushima nuclear disaster 10 years ago, is regarded as one of the pivotal moments during Merkel's 16 years in office. Critics have said the move places a burden on Germany as it seeks to cut carbon emissions to zero by 2045.

"There are other countries that choose differently so it will be easier for them, in some ways, to achieve climate neutrality," Merkel told reporters in Germany. "I still believe that in the long term nuclear energy isn't a sustainable form of energy production."

The phase-out of nuclear power by the end of 2022 has made Germany more reliant on coal over the coming years compared to France or Britain. But the German Government has also committed to ending the burning of coal by 2038, a goal Merkel said could only be achieved by significantly expanding the use of renewable energy.

She rejected the idea that a future Government might reverse the nuclear decision, saying that "for Germany, the die is cast" and called instead for greater efforts to expand production of hydrogen, a carbon-free fuel that experts say will be needed by the country's industry. **AP**

Politics foil replacing hazardous bridge to Jerusalem site

Jerusalem: A rickety bridge allowing access to Jerusalem's holy site is at risk of collapse, according to experts. But the flashpoint shrine's delicate position at ground-zero of the Israeli-Palestinian conflict has prevented its repair for more than a decade.

The tenuous state of the Mughrabi Bridge has raised fears of another disaster months after a stampede at a religious festival in northern Israel left 45 people dead.

Days after the stampede last May, a municipal engineer hired by the Western Wall Heritage Foundation inspected the Mughrabi Bridge. Citing its poor condition, he urged its immediate replacement and authorized its use only until September. With a Supreme Court lawsuit pushing for the structure to be repaired, the government could soon be forced into taking action on a problem that it has long evaded due to its broad diplomatic sensitivities with Jordan, the Palestinians and the broader Muslim world. **AP**

Hong Kong police arrests 5 trade union members for sedition

Hong Kong: Hong Kong police on Thursday arrested five trade union members over children's books they described as seditious, and a court denied bail for four editors and journalists held on charges of endangering national security, as part of a widening crackdown on dissent in the city.

The five who were arrested are members of the General Association of Hong Kong Speech Therapists, according to local media reports.

The association published three children's books that Li Kwai-wah, a senior superintendent of the national security department, said have seditious intent.

The books feature stories that revolve around a village of sheep that has to deal with wolves from a different village. The sheep take action like going on strike or escaping by boat, according to the synopses published on the association's website.

Li said that the stories referenced the 12 Hong Kong activists who were arrested at sea while trying to flee the city, after most of them were charged in connection with massive anti-government protests in 2019.

There was also a story about wolves who are "cruel and try to occupy the area" where the sheep live, and try to kill them, Li said.

"Of course, when we prosecute the case, we are not the one to prove that these materials have actually caused the inciting to others," said Li.

"And the children, maybe because of the information inside ... can turn their mind and develop a moral standard against the society." The 2019 rallies calling for more civil rights and universal suffrage shook Hong Kong for months, often descending into violence between police and protesters. **AP**

Mobile internet disruptions seen in Iran amid water protests

Dubai: Mobile phone internet service in Iran is being disrupted a week into protests in the country's southwest over water shortages, a monitoring group said Thursday, unrest that has seen at least three people killed.

Internet-access advocacy group NetBlocks.org attributed part of the disruption to "state information controls or targeted internet shutdowns." It identified the outages as beginning July 15, when the protests began in Khuzestan amid a drought affecting the oil-rich region neighboring Iraq.

While headline service continues, NetBlocks warned its analysis and user reports were "consistent with a regional internet shutdown intended to control protests."

The effects represents "a near-total internet shutdown that is likely to limit the public's ability to express political discontent or communicate with each other and the outside world," NetBlocks said.

There was no acknowledgement of an internet shutdown in Iranian state media. Iran's mission to the United Nations did not immediately respond to a request for comment. **AP**

G20 environment Ministers meet in Italy amid floods, fires

Naples: With forest fires raging in the US and Russia and floods devastating parts of Western Europe, environment and energy ministers from the Group of 20 industrialised countries gathered Thursday for two days of talks ahead of November's crucial climate change conference. Host Italy is hoping the Naples talks will help spur ambitious goals to be adopted at the COP26 conference in Glasgow, Scotland, which organisers have said represents "the world's last best chance to get runaway climate change under control." The Naples meetings Thursday and Friday are focusing on three main themes: biodiversity and protection of oceans; promoting circular economies, particularly in the fashion and textile sectors. **AP**

Iran bypasses Hormuz Strait to export crude oil

Tehran: Iran on Thursday began exporting crude oil for the first time in the Gulf of Oman, bypassing the strategic Strait of Hormuz.

During a ceremony marking the inauguration of the project, President Hassan Rouhani called the plan "strategic."

Iranian state media described the move as an indication that sanctions imposed by the US were being defeated. Washington placed sanctions on Tehran after former US President Donald Trump pulled his country out of a nuclear deal between Iran and world powers.

The project, which began in 2019 and will cost some \$2 billion in total, helps Iran lessen its dependency on its main oil export terminal on the Persian Gulf island of Kharg. The shortcut also reduces transportation and insurance expenses for oil tankers.

The facility currently allows the pumping of some 30,000 barrels of crude into tankers per hour, via a floating anchored offshore jetty, or single point mooring. It is located some seven kilometers (4.7 miles) off the coast.

"82 per cent of this project has been completed and so far more than 1.2 billion dollars have been spent on this," Oil Minister Jan Zanganeh said. **AP**

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that My client namely Ranjana Jeremiah is hereby cancelling the General Power of attorney dated 7th February 2018 in favour of Biplap Bipal (Which includes their legal heirs) of the property No. B143 C.R. Park New Delhi back portion. Now they or their legal heirs will have no right, title, or any other claim qua the same and all the power will remain in name of my client Ranjana Jeremiah
SajalDhamija (Advocate),
S-265, L.G.F., Greate Kailash1,
New Delhi-110018

PUBLIC NOTICE

This is to inform public in general that Kotak Mahindra bank ltd has organized an auction in below mention respect of Vehicles.
VEHICLES FOR SALE
1) T_LP1512 REG. NO. HR38AA2585-YOM -2020
2) T_LP1512 REG. NO. HR38AA7498-YOM -2020
3) T_LP1512 REG. NO. HR38AA4759-YOM-2020
UNDER HYPOTHECAION WITH M/S KOTAK MAHINDRA BANK IS UNDER SALE IN ITS "AS IS WHERE IS CONDITION" INTERESTED PARTIES CAN GIVE THEIR QUOTATIONS WITH IN 07 DAYS AT
KOTAK MAHINDRA BANK
3RD FLOOR, PLOT NO 7, SECTOR 125, NOIDA-201313 OR
CONTACT : SUNIL KUMAR
KOTAK MAHINDRA BANK LTD.
CONTACT NO. 9643819369

COURT NOTICE

In the court of the Principal Judge Family Court East Singhbhum Jamshedpur Maintenance Case No. 08/2020
Vandana Sharma Petitioner
Versus
Govind Sharma Respondent
To, Govind Sharma S/O Dharamnath Sharma @ Dharamnath Singh R/O Ujjawal Man Power Consultant, 2nd Floor, Sant Nagar East Kailash Nehru Place Delhi, NCR 110065.
Permanent Address: Govind Sharma S/O Dharamnath Sharma @ Dharamnath Singh, R/O Village Rampur Ratnkar Sarsai, P.S. Sarai, P.O. Rampur, Rathakar Dist Vaishali Bihar
Whereas the applicant Vandana Sharma has filed the case in this court U/s 125 of Crp, notice have been issued through the registered post but you have failed to appear before this court. You are hereby directed to appear before this court virtually through https://meet.jit.si/principaljudgeamr on 26th day of July 2021 at 10:30AM, to answer the same failing which the case shall be heard Ex Parte in your absence in accordance with law. Given under my hand and seal of this court 7th Day of July 2021
(Niraj Kumar Srivastav)
Principal Judge Family Court
East Singhbhum Jamshedpur

SUNIL HEALTHCARE LIMITED



Registered Office
38E/252-A, Vijay Tower, Shahpurjat, New Delhi-110049
Email: info@sunilhealthcare.com; website: www.sunilhealthcare.com
CIN No. L24302DL1973PLC189662

Extract of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2021

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		3 Months ended 30.06.2021	3 Months ended 31.03.2021	3 Months ended 30.06.2020	Year Ended 31st March 2021	3 Months ended 30.06.2021	3 Months ended 31.03.2021	3 Months ended 30.06.2020	Year Ended 31st March 2021
		Unaudited	Audited (Refer note. 2)	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited (Refer note. 2)	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	2,636.58	2,393.36	2,114.62	9,525.18	2,675.19	2,445.01	2,176.42	9,583.52
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)-from Continuing Operation	37.09	15.20	1.64	34.94	31.81	(50.51)	(17.90)	(55.32)
3	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)- from Discontinued Operation	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)from Continuing Operation	37.09	15.20	1.64	34.94	31.81	(50.51)	(17.90)	(55.32)
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)- from Discontinued Operation	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)-from Continuing Operation	27.50	6.87	0.06	27.53	20.84	(59.76)	(19.97)	(63.79)
5	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)- from Discontinued Operation	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	27.50	6.87	0.06	27.53	20.84	(59.76)	(19.97)	(63.79)
6	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	27.50	8.85	0.06	29.51	14.60	(39.37)	(21.68)	(88.08)
6	Paid-up equity share capital (Face value Rs.10/- each)	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48	1,025.48
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	3,781.78	-	-	-	3,346.25
8	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each)-from Continuing Operation								
	(a) Basic (Rs.)	0.27	0.07	0.00	0.27	0.20	(0.58)	(0.19)	(0.62)
	(b) Diluted (Rs)	0.27	0.07	0.00	0.27	0.20	(0.58)	(0.19)	(0.62)
9	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each) -from Discontinued Operation								
	(a) Basic (Rs.)	-	-	-	-	-	-	-	-
	(b) Diluted (Rs)	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each)								
	(a) Basic (Rs.)	0.27	0.07	0.00	0.27	0.20	(0.58)	(0.19)	(0.62)
	(b) Diluted (Rs)	0.27	0.07	0.00	0.27	0.20	(0.58)	(0.19)	(0.62)

Notes:
1 COVID - 19 pandemic has caused serious disruption on the global economic and business environment. There is a huge uncertainty with regard to its impact which cannot be reasonably determined at this stage. However, the Company has evaluated and considered to the extent possible the likely impact that may arise from COVID-19 pandemic as well as all event and circumstances upto the date of approval of these Financial results on the carrying value of its assets and liabilities as on 30.06.2021. Based on the current indicators of future economic conditions, the Company estimates to recover the carrying amount of these assets and to discharge its obligation adequate liquidity is available. These estimates are subject to uncertainty and may be affected by the severity and duration of the pandemic. The Company is continuously monitoring any material changes in future economic conditions.
2 The figures for the quarter ended March 31, 2021 are the balance figures between audited figures for the full financial and published year to date figures up to the third quarter of the previous financial year.
3 The figures for the previous periods have been regrouped/ rearranged, wherever considered necessary, to conform current period classifications.
4 The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on July 21, 2021 .

Place : New Delhi
Date : 21.07.2021
Anil Khaitan
Chairman Cum Managing Director
DIN 00759951